UNIVERSITY NEWS 13 OCTOBER 2025

AMAR UJALA PAGE NO NO 2

तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से पात्रों को नहीं मिल रहा राशन

अमर उजाला ब्यूरो

प्रयागराज, सीतापुर, बरेली व झांसी में लविवि की प्रोफेसर के शोध से सामने आई बात

शोध टीम ने सुधार के उपाय भी सुझाए

लखनऊ। प्रदेश के कई जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में कई खामियां पाई गई हैं। प्रयागराज, सीतापुर, बरेली और झांसी में हुए सर्वे व शोध से पता चला कि कई पात्र परिवार, तकनीकी कारणों और प्रशासनिक चूक से राशन पाने से वंचित हैं। वहीं, अपात्र लोग जालसाजी से योजना का लाभ उठा रहे हैं।

लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग की प्रोफेसर रोली मिश्रा और शोधार्थी अंकित उपाध्याय की ओर से इन जिलों में किए गए सर्वे में यह खुलासा हुआ है। डॉ. रोली का शोधपत्र 'वर्तमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली कितनी समावेशी है' प्रतिष्ठित पत्रिका इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में प्रकाशित हुआ है। इसमें बिंदुवार खामियां बताते हुए सुधार के उपाय भी सुझाए गए हैं।

इस तरह की मिलीं खामियां

- अध्ययन में पाया गया कि तकनीकी गड़बड़ियों, आधार आधारित बायोमीट्रिक प्रणाली आदि के कारण कुछ परिवारों के राशन कार्ड रद्द हो गए हैं क्योंकि कार्ड पर दर्ज सदस्यों के आधार नंबर अपडेट नहीं थे।
- चारों जिलों में राशन वितरण में कोटेदारों की ओर से दो से तीन किलो राशन की कटौती आम बात है।
- वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना प्रवासियों के बीच जागरूकता और तकनीकी अड़चनों के कारण प्रभावी नहीं हो पा रही है।

शोधकर्ताओं ने दिए सुझाव

- शोधकर्ताओं ने सरकार को सुझाव दिया है कि लाभार्थियों के डाटा को अपडेट किया जाना चाहिए।
- सरकारी फेयर प्राइस दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए। शिकायत निवारण प्रणाली को प्रभावी तरीके से सक्रिय करने की जरूरत है।

NBT PAGE NO 2

CITY BRIEFS

आनलाइन कोर्सों में 170 एडमिशन

LUCKNOW: एलयू में संचालित आनलाइन आठ कोर्सों में इस बार करीब 170 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है. सेंटर फार आनलाइन एंड डिस्टेंस एजुकेशन के निदेशक प्रोफेसर पियूष भार्गव ने बताया कि जिन विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है, उनके अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है. 15 अक्टूबर से पहले इनकी सूची यूजीसी की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी. 17 अक्टूबर को दोपहर एक बजे आनलाइन इंडक्शन प्रोग्राम होगा. इसका लिंक उनके मोबाइल पर शेयर किया जाएगा. 20 अक्टूबर तक इन सभी को लागिन आइडी व पासवर्ड दे दिया जाएगा ताकि वह पढ़ाई कर सकें.

एलयू में 20 से दीपावली की छुट्टी

लखनऊ विश्वविद्यालय ने रविवार को दीपावली का अवकाश घोषित कर दिया है. लखनऊ विश्वविद्यालय एवं सहयुक्त कालेजों में 20 से 23 अक्टूबर तक दीपावली पर्व की छुट्टी रहेगी. इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है.

HINDUSTAN PAGE NO 8

आधार अपडेट न होने पर रद्द हो रहा परिवार का राशन कार्ड

शोध

लखनऊ, कासं। लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग की प्रोफेसर रोली मिश्रा और अंकित उपाध्याय ने 'वर्तमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली कितनी समावेशी है? ग्रामीण उत्तर प्रदेश से साक्ष्य' शीर्षक से एक महत्वपूर्ण शोध इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली पत्रिका में प्रकाशित किया है।

इस अध्ययन में उत्तर प्रदेश के चार जिलों प्रयागराज, सीतापुर, बरेली और झांसी में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक सर्वेक्षण के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की संरचनात्मक कमियों का विश्लेषण किया गया है। प्रो. रोली मिश्रा के अनुसार, शोध में पाया गया कि तकनीकी और प्रशासनिक अक्षमताओं के कारण कई पात्र लाभार्थी अनुचित रूप से बाहर हो गए।

उदाहरण के लिए, कुछ सदस्यों का आधार अपडेट न होने पर भी पूरे परिवार के राशन कार्ड रद्द कर दिए गए। इसके विपरीत, अपात्र व्यक्तियों ने राशन लाभ लेने के लिए मृत रिश्तेदारों के नाम, भूमि रिकॉर्ड में हेरफेर और फर्जी आय प्रमाण पत्र जैसे छल-छद्म का सहारा लिया। इसके अलावा, 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' योजना भी जागरूकता की कमी और संचालन संबंधी अड़चनों के कारण प्रभावी नहीं हो पा रही है।

AMAR UJALA PAGE NO 10

लोहिया की हिमालय नीति पर हुई चर्चा

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग और डॉ. राम मनोहर लोहिया शोधपीठ की ओर से तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा है। रविवार को सम्मेलन के दूसरे दिन दक्षिण एशिया में भाषा, संस्कृति और क्षेत्र की अंतर्संबंधता पर चर्चा हुई। डीपी. मुखर्जी हॉल, एके. सरन हॉल और फैकल्टी लाउंज में करीब 75 शोधकर्ताओं ने शोध पत्र प्रस्तुत किए। मुख्य व्याख्यान राम मनोहर लोहिया : भारत की हिमालय नीति विषय पर कुलपति प्रो. मनुका खन्ना के मार्गदर्शन में हुआ। प्रो. केएल. शर्मा (जेएनयू), प्रो. पंकज अशोक, प्रो. एके पांडे ने लोहिया के समाजवादी विचारों व हिमालय नीति, महिला प्रवासी मजदूरों की स्थिति पर विस्तार से प्रकाश डाला। (माई सिटी रिपोर्टर)

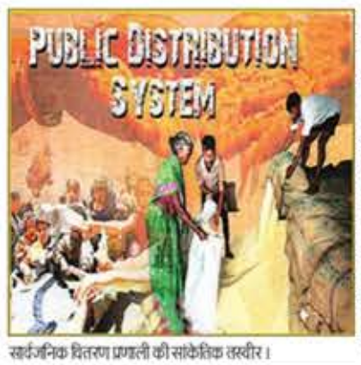

AMRIT VICHAR PAGE NO 8

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सांकेतिक तस्वीर।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की चुनौतियों को किया उजागर

अमृत विचार, लखनऊ: लखनऊ विश्वविद्यालय की अर्थशास्त्र विभाग की प्रोफेसर रोली मिश्रा और अंकित उपाध्याय का शोधपत्र "वर्तमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली कितनी समावेशी है" प्रतिष्ठित पत्रिका इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में प्रकाशित हुआ है। अध्ययन में प्रयागराज, सीतापुर, बरेली और झांसी जिलों में पीडीएस की संरचनात्मक खामियों को उजागर किया गया। अध्ययन में पाया गया कि आधार प्रमाणीकरण की तकनीकी गड़बड़ियों से कई पात्र परिवार वंचित रह गए, जबकि अपात्र लोगों ने जालसाजी कर लाभ लिया। सुझाव दिया गया कि 2011 की जनगणना डेटा को अद्यतन कर लाभार्थियों की सूची सुधारी जाए, उचित मूल्य की दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं।

अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में मंच पर उपस्थित विशेषज्ञ।

दक्षिण एशिया पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन

अमृत विचार, लखनऊ: लविवि में आयोजित तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन तकनीकी सत्र हुआ। लगभग 75 शोधपत्र प्रस्तुतकर्ताओं ने दक्षिण एशियाई परिप्रेक्ष्य में भाषा, संस्कृति, पहचान और क्षेत्रीय परिवर्तन पर विचार साझा किए। मुख्य व्याख्यान 'राममनोहर लोहिया : भारत की हिमालय नीति' विषय पर हुआ। प्रो. केएल शर्मा, प्रो. पंकज अशोक, डॉ. अर्चना वर्मा, प्रो. एसएन पटनायक, प्रो. डीआर साहू उपस्थित रहे।

पोस्टर का विमोचन करते अतिथि।

पोस्टर का हुआ विमोचन

अमृत विचार, लखनऊ: लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय संगोष्ठी 'नव अधिनियमित आपराधिक विधियों का विश्लेषण एवं समीक्षा' का पोस्टर रविवार को विमोचित किया गया। विधि संकायाध्यक्ष एवं अधिष्ठाता प्रो. आर. के. वर्मा ने पोस्टर का विमोचन करते हुए कहा कि संगोष्ठी के माध्यम से नये आपराधिक कानूनों की व्यावहारिक चुनौतियों और प्रभावों पर सार्थक चर्चा होगी। संगोष्ठी के संयोजक प्रो. आर. के. सिंह, उप संयोजक प्रो. आनंद कुमार विश्वकर्मा, आयोजन सचिव प्रो. अनुराग कुमार श्रीवास्तव, उप-आयोजन सचिव डॉ. उग्रसेन वर्मा एवं प्रशांत कुमार चौहान उपस्थित रहे।

DAINIK JAGRAN PAGE NO 25

अपात्र लाभार्थी भी ले रहे फ्री राशन की सुविधा

लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग की ओर से चार जिलों में किए गए शोध अध्ययन में सामने आए तथ्य

जागरण संवाददाता • लखनऊ : सरकार की सख्ती के बाद भी तमाम अपात्र लोग फ्री राशन की सुविधा ले रहे हैं। पर्याप्त जमीन, ट्रैक्टर सहित अन्य सुविधाएं होने के बाद भी फर्जी तरीके से अपना राशनकार्ड बनवा रखा है। वहीं, कई पात्र लाभार्थियों को तकनीकी और प्रशासनिक अक्षमताओं के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली से गलत तरीके से बाहर कर दिया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग की प्रोफेसर रोली मिश्रा व शोधार्थी अंकित उपाध्याय की ओर से नवंबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच प्रदेश के चार जिलों में किए गए शोध अध्ययन में यह तथ्य सामने आए हैं। यह शोध अध्ययन शोध पत्र इकोनामिक एंड पालिटिकल वीकली में प्रकाशित हुआ है।

प्रोफेसर रोली मिश्रा ने बताया कि 'वर्तमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली कितनी समावेशी है? ग्रामीण उत्तर प्रदेश से साक्ष्य' शीर्षक से शोध अध्ययन के लिए प्रयागराज, सीतापुर, बरेली और झांसी का चयन किया गया। यहां के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक सर्वेक्षण कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की संरचनात्मक कमियों का विश्लेषण गया। शोधार्थी अंकित उपाध्याय ने बताया कि चारो जिलों के ग्रामीण क्षेत्र से 75-75 लाभार्थियों से बात की गई। उनसे राशन कार्ड बनने, कितने वर्षों से लाभ ले रहे ? कौन सा राशन कार्ड है ? चावल और गेहूं की गुणवत्ता कैसी है ? आदि सवाल पूछे गए।

सरकारी सेवा से रिटायर फिर भी राशनकार्ड : अध्ययन में पाया गया कि तीन से पांच प्रतिशत अपात्र व्यक्तियों ने राशन लाभ पाने के लिए विभिन्न हथकंडे अपनाए, जैसे मृत रिश्तेदारों के नाम पर वाहन पंजीकरण, भूमि स्वामित्व रिकार्ड में हेरफेर और आय प्रमाणपत्रों की जालसाजी। कई ऐसे मिले जो सरकारी सेवा से रिटायर होने के बाद भी राशनकार्ड बनवाकर लाभ ले रहे। वहीं, यह भी पाया कि कई पात्र लाभार्थियों को तकनीकी और प्रशासनिक अक्षमताओं के कारण पीडीएस से अनुचित रूप से बाहर किया गया। ऐसी समस्याएं विशेष रूप से सीतापुर और बरेली के गांवों में प्रमुख थीं।

कोटेदार कर रहे दो-तीन किलो राशन की कटौती

रिपोर्ट के अनुसार चयनित जिलों के 89 से 90 प्रतिशत लाभार्थियों ने बताया कि राशन वितरण के दौरान कोटेदारों की ओर से प्रति कार्ड दो से तीन किलो राशन की कटौती की गई। जब उनसे शिकायत न करने का कारण पूछा गया, तो एक कार्डधारक ने उत्तर दिया, इनसे दुश्मनी, कौन मोल लेवे? यह प्रतिक्रिया डर और प्रतिशोध की भावना को दर्शाती है। वहीं, कुछ लोगों ने चावल बहुत मोटा दिए जाने की बात कही।

दिए गए सुझाव

2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर लाभार्थी डेटा को अपडेट किया जाए, उचित मूल्य की दुकानों पर सीसी कैमरे लगाए जाएं। लाभार्थी शिकायत निवारण प्रणालियां आफलाइन मोड में पुनः शुरू हों।

NBT PAGE NO 7

2 से 3 किलो कम तौल रहे राशन

राशन की सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर एलयू के सर्वे में दावा

■ NBT रिपोर्ट, लखनऊ

[illegible]

नहीं कर पा रहे विरोध

[illegible]

ये दिए सुझाव

- [illegible]
- उचित मूल्य की दुकानों पर CCTV कैमरे लगवाए जाएं।
- [illegible]
- [illegible]